



चंपकम दोरायराजन मामला और FR और DPSP का विकासक्रम

प्रलिस के लयि:

चंपकम दोरायराजन मामला, मूल अधकार, राज्य की नीतिके नदिशक ततत्व, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16(4), प्रथम संवधान संशोधन अधनियम, अनुच्छेद 15(4), नौवीं अनुसूची, 25वां संवधान संशोधन अधनियम, 1971, अनुच्छेद 31C, अनुच्छेद 39(b) और (c), 42वां संवधान संशोधन अधनियम, 1976

मेन्स के लयि:

मूल अधकारों (FR) और राज्य की नीतिके नदिशक ततत्वों (DPSP) और संबधति न्यायकि नरिणयों के बीच संघर्ष

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यो?

1951 में [मौलकि अधकारों \(FR\)](#) और [राज्य नीतिके नदिशक सदिधांतों \(DPSP\)](#) के बीच संघर्ष का प्रथम उदाहरण प्रस्तुत हुआ था।

चंपकम दोरायराजन केस, 1951 क्या है?

- मामले की पृष्ठभूमि: वर्ष 1948 में, मद्रास सरकार ने सांप्रदायकि साधारण आदेश (GO) पेश कयि, जसिके तहत जात और धर्म के आधार पर शैक्षणकि संस्थानों में सीटें आरक्षणति की गईं।
 - सरकार ने [अनुच्छेद 46](#) को उद्धृत कयि, जसिके अंतर्गत अनुसूचित जातयिों, अनुसूचित जनजातयिों और कमज़ोर वर्गों की शकिषा और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का प्रावधान है।
 - मद्रास की एक महिला चंपकम दोरायराजन ने [समता के अधकार \(अनुच्छेद 14\)](#) का उल्लंघन बताते हुए इस आदेश को [मद्रास उच्च न्यायालय \(HC\)](#) में चुनौती दी।
- [मद्रास उच्च न्यायालय का नरिणय, 1950](#): मद्रास उच्च न्यायालय ने जात और धर्म को वर्गीकरण के आधार के रूप में उपयोग करने के कारण सांप्रदायकि सरकारी आदेश को [असंवैधानकि](#) करार देते हुए रद्द कर दयि और तत्पश्चात् मद्रास सरकार ने [सर्वोच्च न्यायालय](#) में अपील की।
- [सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, 1951](#): सर्वोच्च न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को [बरकरार रखा](#) तथा सांप्रदायकि सरकारी आदेश को [असंवैधानकि](#) घोषति कयि।
 - फैसले में कहा गया कि यह [अनुच्छेद 14 \(समानता का अधकार\)](#) और [अनुच्छेद 15\(1\) \(धर्म, मूलवंश, जात, लयि या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का नषिध\)](#) के तहत मौलकि अधकारों का उल्लंघन है।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय दयि कि [मूल कानून, राज्य पुलसि बलों पर प्रभावी होगा](#) तथा यह सुनिश्चित कयि गया कि [संसद संवैधानकि संशोधनों](#) के माध्यम से [मूल कानून](#) में संशोधन कर सकती है।
- [सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का प्रभाव](#): इस फैसले ने शकिषा में जात-आधारति आरक्षण को रद्द कर दयि, क्योकि संवधान के तहत [केवल सार्वजनकि नौकरयिों में आरक्षण](#) की अनुमति प्रदान की गई थी ([अनुच्छेद 16\(4\)](#))।
 - इसके परिणामस्वरूप शकिषा में आरक्षण बहाल करने के लयि [प्रथम संवधान संशोधन अधनियम, 1951](#) पारति कयि गया।
- [प्रथम संवधान संशोधन अधनियम, 1951](#): सरकार द्वारा [अनुच्छेद 15\(4\)](#) को शामिल करके [अनुच्छेद 15 में संशोधन कयि गया](#), जसिने राज्य को [सामाजकि और शैक्षणकि रूप से पछिडे वर्गों \(SEBC\)](#), [अनुसूचित जातयिों \(SC\)](#) और [अनुसूचित जनजातयिों \(ST\)](#) की उन्नति के लयि वशिष प्रावधान करने की अनुमति दी।
 - इस संशोधन ने [शैक्षणकि संस्थानों में आरक्षण के लयि संवैधानकि आधार प्रदान कयि](#)।

कमज़ोर वर्गों के लयि प्रमुख संवैधानकि प्रावधान क्या हैं?

- [अनुच्छेद 15\(1\)](#): धर्म, मूलवंश, जात, लयि या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का नषिध करता है।

- अनुच्छेद 15(4): SEBC, SC और ST के कल्याण के लिये विशेष प्रावधान करता है, जिससे शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण शामिल है।
- अनुच्छेद 16(4): पछिडे वर्गों के लिये सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण की अनुमति प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 17: असपृश्यता का उन्मूलन करता है।
- अनुच्छेद 46 (DPSP): SC, ST और कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का अधिदेश देता है।

प्रथम संवधान संशोधन अधिनियम, 1951 द्वारा कौन से प्रावधान संशोधित किये गए?

- मौलिक अधिकार:
 - अनुच्छेद 15(4): SEBC, SC और ST के लिये विशेष प्रावधानों की अनुमति दी गई।
 - अनुच्छेद 19: स्वतंत्र भाषण पर उचित प्रतिबंधों का वसतिार (अनुच्छेद 19(2)), जिसमें राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और अपराधों के लिये उकसावा शामिल है।
 - राज्य व्यावसायिक योग्यताएँ निर्धारित कर सकता है तथा राज्य के स्वामित्व वाले नगिर्मों के माध्यम से व्यापार, कारोबार या उद्योग को वनियमिति या राष्ट्रियकृत कर सकता है।
- संसद और राज्य वधिानमंडल:
 - अनुच्छेद 85 और 174: यह सुनिश्चित किया गया कि दो संसदीय या राज्य वधिान सत्रों के बीच का अंतराल छह महीने से अधिक न हो।
 - अनुच्छेद 87 और 176: वधिानमंडल में राष्ट्रपति/राज्यपाल का अभिभाषण अब प्रत्येक आम चुनाव के बाद केवल एक बार और प्रत्येक वर्ष पहले सत्र की शुरुआत में अनिवार्य होगा।
- भूमि सुधार:
 - अनुच्छेद 31A: संपदा और संपत्तिके अधिकार के अधिग्रहण से संबंधित कानूनों को मौलिक अधिकारों के तहत चुनौती दिये जाने से सुरक्षित किया गया।
 - अनुच्छेद 31B: मौलिक अधिकारों के संबंध में सूचीबद्ध कानूनों को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षित करते हुए नौवीं अनुसूची बनाई गई।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति: राष्ट्रपति को प्रत्येक राज्य के लिये अनुसूचित जाति (अनुच्छेद 341) और अनुसूचित जनजाति (अनुच्छेद 342) को अलग-अलग निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया गया।

FR और DPSP के बीच टकराव पर अन्य नरिणय क्या हैं?

- गोलकनाथ मामला, 1967: सर्वोच्च न्यायालय ने चंपकम दोरायराजन मामले में अपने नरिणय को पलटते हुए कहा कि संसदमूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, तथा उनके पूरण संरक्षण को सुनिश्चित किया।
- केशवानंद भारती मामला, 1973:
 - पृष्ठभूमि: 25 वें संवधान संशोधन अधिनियम, 1971 द्वारा अनुच्छेद 31C जोड़ा गया, जिसमें दो प्रमुख प्रावधान थे:
 - संसाधन वितरण पर DPSP को लागू करने के लिये कानून (अनुच्छेद 39 (b) और (c)) को न्यायिक समीक्षा से संरक्षित किया गया था, भले ही वे अनुच्छेद 14, 19, या 31 के तहत प्रदान किये गए FR का उल्लंघन करते हों।
 - अनुच्छेद 39(b) और (c) को लागू करने के लिये बनाया गया कोई भी कानून न्यायिक समीक्षा से संरक्षित था, भले ही वह अपने लक्ष्यों को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाया हो।
 - नरिणय: सर्वोच्च न्यायालय ने पहले प्रावधान को बरकरार रखा, तथा यह सुनिश्चित किया कि अनुच्छेद 39(b) और (c) को लागू करने वाले कानून वैध बने रहेंगे, भले ही वे मौलिक अधिकारों के साथ टकराव में हों।
 - इसने न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाने वाले अनुच्छेद 31C के दूसरे प्रावधान को रद्द कर दिया।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढाँचा की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसके अनुसार संवधान के कुछ मूल सिद्धांतों को संशोधनों के माध्यम से बदला या नष्ट नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिये, न्यायिक समीक्षा, संशोधन की सीमिति शक्ति आदि।
- मनिर्वा मलिस मामला, 1980:
 - पृष्ठभूमि: 42 वें संवधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा अनुच्छेद 31C के संरक्षण को सभी DPSPs तक वसितारित किया गया तथा उन्हें अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत FRs पर प्राथमकता दी गई।
 - नरिणय: सर्वोच्च न्यायालय ने 42 वें संशोधन के तहत अनुच्छेद 31C के वसितार को नरिसुत कर दिया तथा नरिणय दिया कि संवधान के संतुलन को बनाए रखते हुए संवधान के मूल अधिकारों एवं राज्य पुलिस बलों के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन आवश्यक है तथा राज्य पुलिस बलों द्वारा संवधान के मूल अधिकारों को दरकिनार नहीं किया जा सकता है।
- वर्तमान सथिति: FR को DPSP पर वरीयता दी जाती है लेकिन संसद अनुच्छेद 39(b) और 39(c) को लागू करने के लिये अनुच्छेद 14 एवं 19 में संशोधन कर सकती है।

नषिकर्ष

चंपकम दोराईराजन मामले के तहत नरिदेशक तत्त्वों पर मूल अधिकारों की सर्वोच्चता स्थापित की गई, जिससे संवधान संशोधनों और न्यायिक व्याख्याओं पर प्रभाव पड़ा। गोलकनाथ, केशवानंद भारती और मनिर्वा मलिस सहित बाद के फैसलों में FR और DPSP के बीच संतुलन को आकार मिला, जिससे संवधानिक सुरक्षा उपायों के रूप में व्यक्तितगत स्वतंत्रता तथा न्यायिक समीक्षा को बरकरार रखते हुए सामाजिक न्याय सुनिश्चित हुआ।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच टकराव पर सर्वोच्च न्यायालय के बदलते दृष्टिकोण का विश्लेषण कीजिये।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न (PYQs)

????????

प्रश्न: भारतीय संवधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा से संबंधित है? (2020)

- (a) राज्य नीतिके नरिदेशक सदिधांत
- (b) मौलिक अधिकार
- (c) प्रस्तावना
- (d) सातवी अनुसूची

उत्तर: (A)

??????

प्रश्न: “संवधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति सीमिति है और इसे पूरण शक्ति के रूप में वसितारति नहीं कथिा जा सकता है।” इस कथन के प्रकाश में स्पष्ट कीजथिे कि कथिा संवधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद अपनी संशोधन शक्ति का वसितार करके संवधान के मूल ढाँचे को नष्ट कर सकती है? (2019)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/champakam-dorairajan-case-and-evolution-of-frs-and-dpsps>

